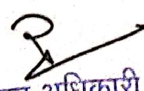


10.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उपस्थित।
बहस सुनी गयी। पत्रावली का प्रबलोकन
किया गया। वादग्रस्त भूमि प्राथमिकता
की आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा
एवं संतुलन की दृष्टि से प्राथमिकता के
पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड की व मौके
की रिष्पति में परिवर्तन किये जाने पर
वाद विविधता बढ़ेगी। तथा प्राथमिकता को
अपूरणीय क्षति होगी।

इस अस्थायी निषेधाज्ञा जारी
कर अप्राथमिकता को पाबंद किये जाते
हैं कि मौजा नोडा के जमाबंदी खा.सं.
96 के ख.सं. 156/2 का कुल रकबा 0.8256
हैक्टर भूमि, जो प्राथमिकता की आराजी
भूमि है, में मूल वाद के फॉरमले तक
अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें। न किसी
अन्य से करावे। प्राथमिकता को काश्र करने
में रुकावट पैदा न करें, न अन्य किसी
व्यक्ति से करावे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति बगर रहे।

पत्रावली में मूल वाद के फॉरमले तक
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली
फॉरमल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा